

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1426 / 2013 / भीलवाड़ा.

2. अपील संख्या - 1426 / 2013 / भीलवाड़ा.

मैरारत बी. एल. चौधरी एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिमाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26 / 09 / 2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 124/वेट/2012-13 व 125/वेट/2012-13 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 28.5.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये धारा 24 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2012 एवं कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये धारा 24 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों आंशिक प्रतिप्रेषित एवं आंशिक अस्वीकार की गई है एवं करमुक्ति शुल्क के बिन्दु पर अपीलों आंशिक अस्वीकार की गई हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों से प्राप्त कुल राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है। संविदा कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त माल, जो वेट चुकाकर खरीद किया गया, उस खरीद राशि में लाभांश व खरीद जोड़कर कर निर्धारित किया गया है।

मनोहर पुरी

4. व्यवहारी द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2009-10 में संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां रुपये 3,14,30,598/- घोषित की हैं। सकल प्राप्तियों में से कर मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय योग्य प्राप्तियां 1,14,69,054/- है। शेष प्राप्तियां रुपये 1,99,61,544/- बिना करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय योग्य प्राप्तियां हैं, अर्थात् संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहणीय है।

5. इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2010-11 में संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां रुपये 3,91,72,777/- घोषित की हैं। सकल प्राप्तियों में से कर मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय योग्य प्राप्तियां 3,14,97,232/- है। शेष प्राप्तियां रुपये 76,75,545/- बिना करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय योग्य प्राप्तियां हैं, जिन पर संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहणीय है।

6. करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि भी शामिल है। करमुक्ति शुल्क से उद्ग्रहण से भिन्न प्राप्तियों में से स्थानान्तरित माल सम्पत्ति की खरीद + लाभांश एवं खर्च जोड़कर कर निर्धारण किया गया है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री एम.पी.शर्मा, कर सलाहकार उपस्थित हुए। बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेश दिनांक 28.5.2013 में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजदूरी राशि पर किसी प्रकार का वेट आरोपित नहीं किया जा सकता है। बिलडिंग कार्य होने से वेट अधिनियम में 30 प्रतिशत मजदूरी कम करनी थी, उसके बाद ही ई.सी. फीस आरोपण योग्य थी। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश किया था, फिर भी हमारी अपीलें खारिज कर दी तथा इस बिन्दु पर अपीलें स्वीकार करने की मांग की।

8. अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये माल की राशि को बढ़ाकर कर निर्धारित किया गया है। किसी भी प्रकार की वृद्धि करने के लिये विशिष्ट नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रार्थी को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी को विशिष्ट नोटिस देने हेतु मामला प्रतिप्रेषित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के अनुसार कर निर्धारण करते समय ही नोटिस देना चाहिये। यदि उस समय नोटिस नहीं दिया गया है तो अब नोटिस नहीं दिया जा सकता। अतः प्रतिप्रेषित आदेश को समाप्त करने की मांग करते हुए अधिक आरोपित कर राशि को निरस्त करने की मांग की है।

नोटिस

9. अपीलाधीन आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण आंशिक प्रतिप्रेषित किये गये हैं, जिसमें प्रतिप्रेषित बिन्दु पर हमारा निवेदन है कि कर निर्धारण वर्ष की समय-सीमा 2 वर्ष ही है। दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 के कर निर्धारण हेतु जो भी कार्यवाही होनी चाहिये, वह दिनांक 31.3.2012 तक ही की जा सकती है। उसके बाद यदि कर निर्धारण अधिकारी इस हेतु पुनः नोटिस देकर सुनवाई करते हैं तो समय-सीमा में नहीं होने से प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1986 आर.टी.सी. 187 प्रस्तुत किया तथा प्रतिप्रेषित बिन्दुओं पर अपीलें स्वीकार करने की मांग की।

10. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 338/99 व 339/99 कर निर्धारण वर्ष 93-94 एवं 94-95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बारां बनाम केसरीमल रतनलाल छाबड़ा निर्णय दिनांक 25.11.2002 का उल्लेख किया गया। इसी क्रम में मीठालाल ओमप्रकाश बालोतरा के मामले में दिये गये निर्णय का दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

11. अन्य न्यायिक दृष्टान्त अरविन्द एण्ड कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर बनाम किस्तूरमल गुलाबचन्द प्रस्तुत किया।

12. ई.सी. से सम्बन्धित कुल आवर्त राशि में से मजदूरी की राशि 30 प्रतिशत पर आरोपित 1.5 प्रतिशत से करमुक्ति शुल्क को अपास्त करने की मांग की है।

13. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट चुकाकर क्रय किये गये माल में खर्च व लामांश जोड़कर, बढ़ायी गयी राशि पर आरोपित वैट राशि को निरस्त करने की मांग की है।

14. लिखित बहस में वैट अधिनियम की धारा 24(1) को उद्धृत किया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48, 48 व 50 का उल्लेख करते हुए सन्दर्भ दिया।

15. उक्त प्रावधानों के तहत कर निर्धारण अधिकारी को अतिरिक्त करदेयता निर्धारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अब अपारत योग्य है।

16. अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण के लिये उक्त बाध्यकारी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया है, जो अपास्त योग्य है।



Handwritten signature or mark at the top right of the page.

17. लिखित बरस के बिन्दु संख्या 5 में अधील निर्णय में सुनवाई का अवसर दिव्य विना आयोजित शारित के बिन्दु पर भी प्रकरण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रतिवित किया है।

18. मीडिक बरस के समय माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1999) 114 एस.टी.सी. 265 गारुडर एंड कम्पनी बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य की प्रति अपने पक्ष में प्रस्तुत की।

19. प्रत्यक्षी विभाग की और विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अधीनस्थ आदेश का समर्थन किया। करमुविता का विकल्प लिया जाना एक स्वीच्छक कृत्य है तथा करमुविता का विकल्प लिये जाने के बाद इस हेतु प्राप्ति पर विहित मुविता मुविता कर दर से मुविता शुरूक देसला जाती है।

20. उभयपक्ष की बरस पर मान किया गया एवं पत्रावलिओं का अवलोकन किया गया।

21. संकर्म सविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एक.12(63)एकडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म सविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म सविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्घाटन करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुविता दी गई है। अवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दाखिल का गृहणन मुविता शुरूक के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुविता शुरूक की सविदा इस हेतु घोषित ठेके की सविदा पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुविता शुरूक उद्घाटनीय है। अवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी सविदा को एटने का एक देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञप्त नहीं है।

22. अधिसूचना क्रमांक एक.12(63)एकडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 एवं शालिका के कॉलम 1, 2 व 3 निम्न प्रकार है :-

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) subject to the following conditions, namely:-

(5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-

(i) where an awardee is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awardee from each bill of payment to be made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awardee before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

(ii) where the awardee is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awardee, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;

(iii) the amount already deducted by the awardee in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted;

| Item No. | Description of work contract | Rate of exemption fee % of the total value of the contract |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities. | 0.25 % |
| 2. | Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system. | 1.50 % |
| 3. | works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material. | 2.25 % |
| 4. | Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3. | 3.00 % |

हस्ताक्षर

23. उक्त अधिसूचना में तालिका के कॉलम संख्या 3 से नली-भांति स्पष्ट है कि इस हेतु कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.-1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है :-

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act/I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and his status

24. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। यह निर्णय इस निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये "पण्यवर्त" के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स विल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एस.टी.सी. 370 को Reproduce किया गया है। इसमें "पण्यवर्त" पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। अपीलार्थी का प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि का है। अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं होती है।

25. अपीलार्थी व्यवहारी के ठेका कार्य में प्रयुक्त माल की कीमत का निर्धारण करते समय खरीद में लाभांश व खर्च जोड़कर माल की कीमत का आकलन किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपील बहस के समय प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। संदर्भित निर्णयों में व्यवहारी द्वारा सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिये देय विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे। दिये गये निर्णयों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 में कर निर्धारण आदेश पारित करने के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था है। अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद नहीं करता है।

न तोडा

—: 7 :- 1-2 अर्धल संख्या-1425/2013 एवं 1426/2013/भीलवाडी

26. भारतीय राजस्व विभाजन आयोग द्वारा जारी की गई (2003) 6 टीएम 151 सी.टी.ओ., सुन-ए, भीलवाडी एवं राजस्थान एंड कर्णाटकों में यूनाइटेड का अर्धल विधि को संशोधन में निम्नलिखित निर्देश पारित किया है :-

"Since by the order of the appellate authority set aside the original order of the assessing authority on the ground of violation of principles of natural justice and an opportunity of hearing was given to the assessee and thereafter, fresh order has been passed by the assessing authority then this court is not inclined to interfere in a matter where only opportunity of hearing was granted to the assessee once more and, thereafter, an order has been passed by the assessing authority and if the petitioner is aggrieved against fresh order, he can challenge the order by filing an appeal."

27. भारतीय राजस्व विभाजन आयोग द्वारा जारी की गई (2010) 29 टी.एम.सी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. का नाम नए कर्षक/संशोधन एंड कर्णाटकों में राजस्थान

की है कि -

"Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made within the State of Rajasthan. The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer."

28. अर्धल संख्या 1426/2013 की संशोधित प्रकरण में आई.टी.ओ. वकील के विरुद्ध भारतीय राजस्व विभाजन आयोग ने आर्थिक इंडिया (1961) 12 ए.एम.सी.ओ. 114 राजस्थान संदर्भ एंड राज-ए एंड कर्णाटकों राजस्थान एंड कर्णाटकों में

राजस्थान की है कि -

"The exemption under a licence granted to a dealer in cotton under section 5 of the Madras General Sales Tax Act, 1939, is conditional upon the observance of the conditions prescribed and upon the restrictions which are imposed by and under the Act or in the rules or in the licence itself. A licensee is therefore exempt from assessment as long as he conforms to the conditions of the licence and he is not entitled to exemption if the conditions upon which the licence is given are not fulfilled. The use of the words "subject to" has reference to effectuating the intention of the law and the correct meaning is "conditional upon".

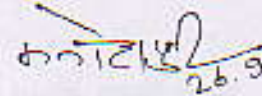
मन्तराज

29. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय का undertaking स्वीकार किया है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेगा। व्यवहारी इन्पुट टैक्स क्रेडिट का बलेम करने के लिये पात्र नहीं है। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरुद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स बलेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (2010) 29 वी.एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी ठेकेदार की कर निर्धारण वर्ष 2010-11 में संविदा प्राप्तियां राशि रूपये 3,14,97,232/-, वर्ष 2009-10 में संविदा प्राप्तियां राशि रूपये 1,14,69,054/-, मुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित है। इन प्राप्तियों पर विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी है। मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन संविदा प्राप्तियों में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने माल की कीमत के निर्धारण के बिन्दु पर व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये हैं, जो पैरा 26 में अंकित व्यवस्था के अनुरूप है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

31. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

32. निर्णय सुनाया गया।


26.9.2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य